SATISH AGARWAL): Please. Yes, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue of fishermen of Tamil Nadu, who had been killed by the Sri Lankan Navy, raised by the senior Member, Shri Gopalsamy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): It was some time back.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will be very brief, Sir. These incidents are taking place because of the rights of Kachathivu. The right of occupation of Kachathivu has been given to the Sri Lankan Government by the Indian Government long back. (*Interruptions*)...

SHRI V. GOPALSAMY: It was a sell-out by the Government of India. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Gopalsamy, there will be no end to this type of debate. This is only a Special Mention.

SHRI V. NARAYANASAMY: We have also raised this issue at the time of the debate on the President's Address. We have made this issue very clear. We wanted a specific clause that the Indian fishermen, who go for fishing in Kachathivu, should be given the right to drag their net. It is there in the agreement itself. But the Sri Lankan Government is violating it. They are not allowing our fishermen to drag their net. Under the guise that our fishermen are in the Sri Lankan territorial waters they are killing our fishermen. There is another aspect behind this. The LTTE does not want our fishermen to go there so that the smuggling activities are not hampered. That is why they are killing our fishermen. Therefore, I request the Government of India to intervene in the matter and see that the lives of our fishermen are protected. Sir, the Navy should be deployed there so that the lives of the fishermen could be protected.

Likely infiltration of ISI agents on the occassion of the celebration of a fair in Jammu

श्री राज नाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): मैं बहुत ही कम शब्दों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह भारत सरकार भी स्वीकार करती है कि आईएसआई घुसपैठियों की गतिविधियां भारत में चल रही हैं। अब आईएसआई नए-नए तरीके अपने एजेंटों को बनाने के लिये तथा घुसपैठियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने के लिए अपना रही है। अभी एक हाल की घटना का उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझता हूं कि बिहार के कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक श्री पंकज कुमार सिन्हा का अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद कई महीनों तक उनको हिरासत में रखा गया और बराबर उनको आईएसआई द्वारा यह प्रलोभन दिया जाता रहा कि तुम एक करोड़ रुपया ले लो और भारत में रहकर आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करो। अब इस प्रकार के सारे तरीकों को छोड़कर आईएसआई धार्मिक प्रयोजनों के माध्यम से घुसपैठियों को भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कराने की योजना बना चुकी है।

मान्यवर, भारत की सीमा में जम्मू के पास और पाकिस्तान की सीमा के अंतर्गत आने वाला जो सियालकोट जिला है, उसमें सैयदावली एक क्षेत्र है, जहां पर कि प्रतिवर्ष, कई बरसों से, 16 जून से लेकर 23 जून तक, बाबा चमलयाल का एक मेला आयोजित होता है लेकिन 23 तारीख का बड़े पैमाने पर जो मेला आयोजित होता है वह भारत की सीमा के अंतर्गत रामगढ़ सैक्टर में आयोजित होता है और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर बाबा चमलयाल का दर्शन करने के लिये आते हैं। एक लोक-कथा भी है उस स्थान के बारे में कि जिस व्यक्ति को स्किन डिसीज़ हो जाए, चर्म-रोग हो जाए, जिसे चम्बल रोग कहते हैं, यदि वह बाबा चमलयाल के स्थान पर चला जाए और वहां की मिट्टी का सेवन करे और वहां के जल का सेवन करे—मिट्टी को कहते हैं शक्कर और जल को कहते हैं शर्बत, यानी शक्कर और शर्बत का जो सेवन करेगा, उसका चर्म-रोग ठीक हो जाएगा, यह धारणा बनी हुई है। यदि हजारों की संख्या में भारत के श्रद्धालु वहां पर जाते हैं तो लाखों की संख्या में पाकिस्तान के श्रद्धालु भी वहां पर श्रद्धापूर्वक जाते हैं। लेकिन यह जानकारी मिली है, समाचार पत्रों में

भी यह समाचार प्रकाशित हो चुका है कि कुछ आईएसआई के अधिकारियों के द्वारा सीमा पर इस समय गश्त लगाई जा रही है ताकि 23 जून को, जिस दिन यह मेला बड़े पैमाने पर आयोजित होगा तो भारी संख्या में आईएसआई के घुसपैठियों को भारत की सीमा के अंदर भेजा जा सके। मान्यवर, आज भी एक फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान की और आईएसआई, इन दोनों इंटेलिजेंट यूनिट्स के अधिकारियों की गश्त भी चल रही है और वहां पर वेरी लाइट दागी जा रही है—वेरी लाइट इस प्रकार का सिस्टम है ताकि उसको आकाश में, हवा में छोड़ा जाता है और उसके माध्यम से यह संकेत दिया जाता है शरण दिलाने वालों को कि जिस स्थान पर यह जाकर गिरेगा, उसी स्थान से घुसपैठिए भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे। यह प्रयोग वहां पर खुले आम चल रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। बीएसएफ को यदि सीमा पर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए, मिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात की जानी चाहिए ताकि हम आईएसआई के नापाक इरादों को विफल कर सके, जो कि भारत की एकता व अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और पाकिस्तान यह चाल चल रहा है। अमरीका की इसमें शह है लेकिन मान्यवर, यह हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जब अमरीका गए तो जैसा कि अभी माथुर साहब ने कहा था कि टेररिस्ट देश पाकिस्तान को घोषित किए जाने के संबंध में जिस प्रकार से उनको दलील दी जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से आग्रह करना चाहिए था, जिस प्रकार से प्रेशर बिल्ड-अप करना चाहिए था, वह उस प्रेशर को बिल्ड-अप नहीं कर पाए।

अतः मान्यवर, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सीमा पर चौकसी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि घुसपैठियों के प्रवेश को रोका जा सके। धन्यवाद।

Power Ministry's negotiations with Enron, A U.S. Multinational

SHRI K. R. MALKANI (Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of this august House to a very dubious deal that is being worked out by the Government of India; on this side, it is the Power Ministry—its ally in this case is the Maharashtra Government—and on the other side is a foreign company, Enron. The idea is to import, to pipe, gas all the way from the Persian Gulf to India and use it for generating power. It has been found that the installation cost per mega watt will be 100 per cent higher in this case than is the case today. It has also been estimated that the unit cost of power will be twice as much as it is today. We all know how much the World Bank is interested in multinational corporations. But even the World Bank had rejected this scheme and called it economically and technically not feasible. Still, the Government is proceeding with it. The National Working Group on the power sector which consists of some of the top-most technicians in the country, has also rejected it and taken exception to it.

Now, a few questions arise. We have gas in the Bombay High and we are flaring it away Government does not have the money to pipe that gas from Bombay High to Bombay and use it. But it wants to import gas all the way from Oman. This is out-Tughlaqing Tughlaq.

This Government has undertaken to give a guarantee of 16 per cent return—it is not even a simple guarantee, it is a sovereign guarantee. The point is, the Government of India does not give any guarantee to any Indian project; the United States Government does not give any guarantee to any American project. Then, how is it that the Government of India is giving this kind of a guarantee to a foreign company? "Secondly, what is this new concept" sovereign guarantee? I am told that if the clients, that is, if the consumers of power, did not pay their